

**न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं**

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी  
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 266/2022

जवाहरलाल गुप्ता उम्र 73 वर्ष पुत्र श्री रतनलाल गुप्ता, जाति महाजन, निवासी सुलताना, हाल टिल्ली मन्दिर के पास, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

---आवेदक

बनाम

1. श्री संदीप चौधरी, उपखण्ड अधिकारी चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिडावा, जिला झुंझुनूं।
3. मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथ जी सुलताना जरिये पुजारी
4. हाजी हकीमूदीन पुत्र सफी, जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

--- अनावेदकगण

---

अन्तरण प्रार्थना पत्र अ0 धारा 235 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 मुकदमा उनवानी जवाहरलाल बनाम राजस्थान सरकार वगैरह मु0नं0 180/2017 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिडावा प्रकरण वाद घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

---

उपस्थित:-

1. श्री दलीप कुमार सैनी, अभिभाषक- आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट- अनावेदक सं0 4 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- अनावेदक सं0 1 लगायत 3 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 06.10.2022

अन्तरण प्रार्थना निम्न प्रकार से पेश है कि निम्न वर्णित प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा के यहां लम्बित है :-

मु0 उनवानी	-	जवाहरलाल बनाम राजस्थान सरकार
मु0नं0	-	180/2017
प्रकरण	-	वाद घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
आगामी पेशी	-	28/07/2022

प्रार्थी आवेदक ने उक्त उपखण्ड अधिकारी चिडावा के यहां एक वाद प्रतिवादीगण राजस्थान सरकार व मूर्ति मंदिर के विरुद्ध पेश किया था जिसमें प्रार्थी को गवाह हेतु शपथ पत्र पेश करने थे परन्तु अप्रार्थी नं0 4 हाजी हकीमुदीन ने एक प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 दिनांक 12.04.2022 को पेश किया पर प्रार्थी को अ0 आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का जबाब हेतु दिनांक 18.04.2022 को आगामी तारीख पेशी दी गई। प्रार्थी/आवेदक की ओर से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी चिडावा को कहा गया प्रार्थी को नियमित रूप से तारीख दी जावे लेकिन पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी ने गुस्सा करके दिनांक 18.04.2022 को पत्रावली जबाब में लगा दी। दिनांक 18.04.2022 को अनावेदक नम्बर 4 जो ग्राम पंचायत सुलताना का पूर्व सरपंच है ने आवेदक को धमकी दी की हमारी अनावेदक नम्बर 1 पीठासीन अधिकारी से

  
जिला कलक्टर झुंझुनूं

बात हो चुकी है। आवेदक ने अनावेदक नं० 4 को अनावेदक नं० 1 के घर से बाहर आते जाते देखा है तथा चैम्बर में भी आते जाते देखा है। अनावेदक नं० 4 ने आवेदक को कहा कि हमारा प्रार्थना पत्र अ० आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार होगा हमारी बात हो चुकी है। अनावेदक नं० 4 उपखण्ड अधिकारी चिडावा के यहा अन्य कई प्रकरणों में भी अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किये है जिसमे ज्यादातर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये है। मौजूदा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित प्रकरण में अनावेदक नम्बर 1 पीठासीन अधिकारी की मानसिकता उक्त प्रकरण पत्र अ० धारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार करने की रही है तथा तारीख पेशी भी अधिकतर 7-7 दिवस की दी है तथा दिनांक 28.07.2022 को लगा दी। उपरोक्त प्रकार से अनावेदक नं० 4 द्वारा दी गई धमकी व अनावेदक नम्बर 1 की मानसिकता को देखते हुये आवेदक को अनावेदक नं० 1 से उक्त प्रकरण में निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इस कारण मौजूदा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि मौजूदा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित दावा उपखण्ड अधिकारी चिडावा से अन्य न्यायालय में अंतरित कि जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी चिडावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी चिडावा ने पत्रांक 650 दिनांक 09.09.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बिन्दूवार अवगत कराया कि बिन्दू सं० 1 स्वीकार है। बिन्दू सं० 2 में वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है। बिन्दू सं० 3 में वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है। शेष प्रश्न में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी०पी०सी० में दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही निर्णय किया जाता है। बिन्दू सं० 4 में वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है और प्रार्थी द्वारा लगाये गये समस्त आरोप गलत होने पर अस्वीकार है और उक्त प्रकरण में देरी करना चाहता है। और शेष प्रश्न में अगर उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नहीं है। बिन्दू सं० 5 व 6 कानूनी है जबाब की आवश्यकता नहीं है। आवेदक द्वारा उनवानी वाद पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय में करवाना चाहता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि चिडावा के यहां लम्बित है मु० उनवानी जवाहरलाल बनाम राजस्थान सरकार मु० नं० 180/2017 प्रकरण बाबत वाद घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थी आवेदक ने उक्त उपखण्ड अधिकारी चिडावा के यहां एक वाद प्रतिवादीगण राजस्थान सरकार व मूर्ति मंदिर के विरुद्ध पेश किया था जिसमें प्रार्थी को गवाह हेतु शपथ पत्र पेश करने थे परन्तु अप्रार्थी नं० 4 हाजी हकीमुद्दीन ने एक प्रार्थना पत्र अ० आदेश 1 नियम 10 सी०पी०सी० दिनांक 12.04.2022 को पेश किया पर प्रार्थी को अ० आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का जबाब हेतु दिनांक 18.04.2022 को आगामी तारीख पेशी दी गई। प्रार्थी/आवेदक की ओर से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी चिडावा को कहा गया कि प्रार्थी को नियमित रूप से तारीख दी जावे लेकिन पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी ने गुस्सा करके दिनांक 18.04.2022 को पत्रावली जबाब में लगा दी। दिनांक 18.04.2022 को अनावेदक नम्बर 4 जो ग्राम पंचायत सुलताना का पूर्व सरपंच है ने आवेदक को धमकी दी की हमारी अनावेदक नम्बर 1 पीठासीन अधिकारी से बात हो चुकी है। आवेदक ने अनावेदक नं० 4 को अनावेदक नं० 1 के घर से बाहर आते जाते देखा है तथा चैम्बर में भी आते जाते देखा है। अनावेदक नं० 4 ने आवेदक को कहा कि हमारा प्रार्थना पत्र अ० आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार होगा हमारी बात हो चुकी है। अनावेदक नं० 4 उपखण्ड अधिकारी चिडावा के यहा अन्य कई प्रकरणों में भी अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किये है जिसमे ज्यादातर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये है। मौजूदा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित प्रकरण में अनावेदक नम्बर 1 पीठासीन अधिकारी की मानसिकता उक्त प्रकरण पत्र अ० धारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार करने की रही है तथा तारीख पेशी भी अधिकतर 7-7 दिवस की दी है तथा दिनांक 28.07.2022 को लगा

जिला कलेक्टर झुझरू

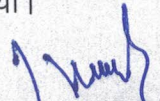
दा। उपरोक्त प्रकार से अनावेदक नं० 4 द्वारा दी गई धमकी व अनावेदक नम्बर 1 की मानसिकता को देखते हुये आवेदक को अनावेदक नं० 1 से उक्त प्रकरण में निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इस कारण मौजूदा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किया जाना न्यायोचित है। अतः मौजूदा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित दावा उपखण्ड अधिकारी चिडावा से अन्य न्यायालय में अंतरित कि जावे।

वकील अप्रार्थी सं० 1 लगायत 3 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। फिर भी प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

वकील अप्रार्थी सं० 4 ने वकील प्रार्थी के कथनों का समर्थन किया तथा कथन किया कि प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी, चिडावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मु० उनवानी जवाहरलाल बनाम राजस्थान सरकार मु० नं० 180/2017 प्रकरण बाबत वाद घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, चिडावा मु० उनवानी जवाहरलाल बनाम राजस्थान सरकार मु० नं० 180/2017 प्रकरण बाबत वाद घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। प्रार्थी सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के न्यायालय में दिनांक 03.11.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( एल०एस०कुडी )  
जिला कलक्टर, झुंझुनूं  
जिला कलक्टर झुंझुनूं